

प्रपत्र

श्रीमती नीरा गादय,
प्रमुख राज्य शिक्षा
उत्तर प्रदेश शासन।

सीमा में

- 1- शिक्षा निदेशक (माओ)
उओप्रओ, लखनऊ।
- 2- निदेशक (बेसिक शिक्षा)
उओप्रओ, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-8

लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2001

विषय- प्रदेश के प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को
घयन वेतनमान व प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संC-वेओआओ-2- 1262/दस-2001--
53 / 2001, दिनांक 20 जुलाई, 2001 सम्पटित शासनादेश
संओ-वेओआओ-2-1432/दस-2001- 53/2001, दिनांक 08 अगस्त, 2001 एवं
शासनादेश संख्या -वेओआओ-2/1650/दस-2001- 53/2001 दिनांक 03 सितम्बर,
2001 के प्रस्तर 2 (2) के अनुक्रम में राज्यपाल महोदय सम्यक विचारोपरान्त बेसिक
शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा के ऐसे शिक्षकों जो दिनांक 01 जुलाई, 2001 को सेवारत
थे अथवा इसके उपरान्त नियुक्त हुये हो, को घयन वेतनमान व प्रोन्नति वेतनमान
निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(क) बेसिक शिक्षा-

- (1) प्राथमिक शिक्षकों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक
सेवा पूर्ण करने पर घयन वेतनमान अनुमन्य कराया जायेगा।
- (2) घयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवापूर्ण करने के उपरान्त
प्रोन्नत वेतनमान घयन वेतनमान के पदधारकों की संख्या में 20
प्रतिशत की सीमा तक देय होगा।
- (3) प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक वर्ष में एक बार बेसिक
शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक घयन समिति का गठन किया

जायेगा जो शिक्षकों की उपयुक्तता पर विचार कर जायेगा। जिसके आधार पर नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

- (4) उपरोक्त प्रक्रिया प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक, प्रधानाध्यापक प्राध्यापक विद्यालय के प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के रायब म की जायेगी।
- (5) यदि किसी वर्ष में प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु प्रतीत हो कि कार्यरत शिक्षकों की संख्या अधिक होगी तो प्रोन्नति वेतनमान / प्रधानाध्यापकों की अपने पद पर मौलिक नियुक्ति की जायेगी। कमानुसार सूची बनाकर प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

(ख) माध्यमिक शिक्षा-

- (1) माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों / प्राध्यापकों के वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा तथा ध्यान वेतनमान में प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने पर प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।
- (2) अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक वर्ष में एक बार जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में तथा राजकीय विद्यालयों के एल0टी0 शिक्षकों के लिए संबंधित मण्डल के संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एवं राजकीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के संवर्ध में शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में एक समन समिति का गठन किया जायेगा। जो शिक्षकों की उपयुक्तता पर विचार कर अपनी संस्तुति देगी। इस संस्तुति के आधार पर संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा वेतनमान स्वीकृत करने के आदेश जारी किये जायेंगे।
- (3) शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत एल0टी0 शिक्षकों को प्रोन्नति वेतनमान उसी दशा में स्वीकृत किया जायेगा जब एल0टी0 शिक्षकों द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर ली गयी हो।

(1) इस प्रकार के प्रमाणों के आधार पर वेतनमान में 10 वर्ष के
सत्यापन के सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान में निम्न
जायेगा।

चयन/प्रोन्नत वेतनमान की अनुमन्यता के फलस्वरूप
सम्बन्धित शिक्षक का वेतन निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

(1) दिनांक 01-01-1996 को चयन / प्रोन्नत वेतनमान में कार्यरत
शिक्षकों का वेतन, शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-1432
/दस-2001- 53/2001, दिनांक 08 अगस्त, 2001 में शासनादेश
संख्या-वे0आ0-2- 1650/दस -2001 -53/ 2001, दिनांक 0
सितम्बर, 2001 में जारी व्यवस्था के अधीन सीधे संशोधित चयन/
प्रोन्नत वेतनमान में निर्धारित किया जायेगा।

(2) दिनांक 01-01-1996 के बाद की तिथि से चयन वेतनमान की
अनुमन्यता के मामले में सम्बन्धित शिक्षक का वेतन, साधारण
वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से, चयन वेतनमान में अगले प्रक्रम पर
निर्धारित किया जायेगा।

(3) दिनांक 01-01-1996 के बाद की तिथि से वैयक्तिक प्रोन्नत
वेतनमान की अनुमन्यता के मामले में सम्बन्धित शिक्षक का वेतन,
चयन वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से, प्रोन्नत वेतनमान में अगले
प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(4) अवशेषों का भुगतान शासनादेश संख्या- वे0आ0-
2-1432/दस-2001- 53 /2001 दिनांक 08 अगस्त, 2001 के
प्रस्ताव (2) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

उपरोक्त शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1432/दस-2001-53/2001
दिनांक 08 अगस्त 2001 के प्रस्ताव (2) और शासनादेश संख्या
वे0आ0-2-1650/दस-2001-53/2001 दिनांक 01 सितम्बर 2001 के
प्रस्ताव (2) को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जो उनके अशासकीय पत्र

संख्या-ए-11-2292/वस 2001

दिनांक 20.12.2001

किय जा रहे हैं।

महोदय

(नीरा यादव)

प्रमुख सचिव।

संख्या-4507 (1/15-E-2001, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के

लिए-

(1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उ०प्र०, लखनऊ।

(2) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० इलाहाबाद।

(5) समस्त प्रमुख कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(6) समस्त माध्यमिक शिक्षा निदेशक/माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।

(7) समस्त जिला बोर्ड शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(8) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

(9) प्रधानाचार्य, डी०ए०टी० (एल०टी०) प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर।

(10) प्रधानाचार्य, किशोरी रंगण (एल०टी०) प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ।

(11) प्रधानाचार्य, के०पी० (एल०टी०) प्रशिक्षण महाविद्यालय, मथुरा।

(12) प्रधानाचार्य, एल०टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।

(13) समस्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार

कचहरी रोड, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

(श्याम सुन्दर अग्निहोत्री)
संयुक्त सचिव